

प्रेषक,

सुबर्द्धन
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियों,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1

देहरादून: दिनांक 30 नवम्बर, 2012

विषय:-सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत सामान्य कृषकों, लघु एवं सीमान्त तथा बीपीएल परिवारों को सहकारी बैंकों/संस्थाओं द्वारा कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या-3502/अधि0सं0का0/सह0सं0यो0/2012-13 दिनांक 05 अक्टूबर, 2012, पत्र संख्या:-3033/अधि0सं0का0/सह0सं0यो0/2012-13 दिनांक 18 सितम्बर, 2012, मूल्यांकन अध्ययन सम्बन्धी नियोजन विभाग के पत्र संख्या-1148/250/रा0यो0आ0/मू0/अ0/2011 दिनांक 15.10.2012 तथा नाबार्ड के परिपत्र संख्या:-एनबी/56/पीसीडी-27/2012 दिनांक 09.10.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फसली/कृषि ऋण के साथ ही कृषियेत्तर ऋण यथा कृषि निवेश, औद्यानिक, डेरी विकास, पशुपालन, बेमौसमी सब्जी, मशरूम, चाय, रेशम उत्पादन, मत्स्य व मौन पालन, ट्रैक्टर कय व पत्रकारों को कम्प्यूटर कय पर रुपये 50,000.00 तक पांच प्रतिशत तथा रुपये 50,000.00 से 3.00 लाख तक 5.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण अनुमन्य कराने हेतु सहकारी सहभागिता योजना को दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2015 तक (चालू वित्तीय वर्ष सहित तीन वर्ष तक) क्रियान्वित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से समितियों के माध्यम से स्वीकृत सहकारी ऋणों को प्रश्नगत योजना से आच्छादित समझा जायेगा। योजना का लक्ष्य समूह तथा क्रियान्वयन की सीमा निम्नवत् होंगी:-

- (1) योजनान्तर्गत सामान्य, लघु एवं सीमान्त कृषक तथा बीपीएल परिवार के कृषक आच्छादित होंगे तथा एक परिवार के एक ही सदस्य को योजना का लाभ अनुमन्य होगा।
- (2) सामान्य कृषकों, लघु एवं सीमान्त कृषक तथा बीपीएल परिवार का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/ घोषित एजेन्सी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा।
- (3) उक्त योजना का लाभ सहकारी बकायेदार सदस्यों को अनुमन्य नहीं होगा।
- (4) यदि पात्र लाभार्थी/ कृषकों को योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किया जाता है और वह अपने ऋण का भुगतान निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नहीं कर पाता है, तो उस सदस्य को उक्त योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा और उससे चालू सामान्य ब्याज दर के अनुसार वसूली की जायेगी।
- (5) आवास ऋण की अधिकतम सीमा योजनान्तर्गत रुपये 1.00 लाख (रुपये एक लाख) होगी और किसी भी परिवार से लाभार्थी को एक बार ही भवन निर्माण/विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध होगा।
- (6) योजना दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से दिनांक 31 मार्च, 2015 तक स्वीकृत ऋणों पर लागू होगी। इसके अतिरिक्त पूर्व वर्षों में वितरित अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऐसे ऋण जिनकी वसूली अभी बाकी बाकी है तथा लाभार्थी द्वारा समय से किस्तों का भुगतान किया जा रहा है (बकाया ऋण की धनराशि को छोड़कर) पर भी योजना लागू रहेगी।
- (7) ट्रैक्टर/कृषि यन्त्रों हेतु वितरित किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा 5.00 लाख होगी तथा किसी भी परिवार के मात्र एक सदस्य को केवल एक बार के लिये उक्त ऋण अनुमन्य होगा।
- (8) सीमान्त/लघु तथा श्रमजीवी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के वैयक्तिक उपयोग हेतु कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर आदि कय हेतु वितरित किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा रुपये 0.50 लाख

for

अथवा कुल कय मूल्य का 85 प्रतिशत जो भी कम हो, की सीमा तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

- (9) योजनान्तर्गत वर्ष में वितरित ऋणों की तीन वर्षों में देय किस्तों तक ही राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान देय होगा। आगामी वर्षों में सामान्य लागू ब्याज दरों पर ऋण की वसूली की जायेगी।
- (10) फसली ऋणों के लिये निर्धारित अर्धवार्षिक/वार्षिक भुगतान के अतिरिक्त अन्य ऋणों पर रियायती दरों पर ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी, ताकि दिनांक 31 मार्च, 2015 तक स्वीकृत ऋणों का निपटारा समय से किया जा सके।
- (11) योजना के अन्तर्गत अल्पकालीन फसली ऋण रुपये 50,000.00 तक 5.0 प्रतिशत तथा रुपये 50,000.00 से 3.00 लाख तक 5.5 प्रतिशत ब्याज दर पर अनुमन्य होगा। अल्पकालीन/फसली ऋणों के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों की सीमा, नाबार्ड से रियायती दरों पर प्राप्त ऋण के विरुद्ध एवं बैंकों को निर्धारित वार्षिक प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता की गणना कर सहकारी बैंकों के लिये ऋण पर लागू दरों के सापेक्ष आंकलित की गयी अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा चार प्रतिशत की सीमा तक ब्याज अनुदान अनुमन्य कराया जायेगा।

3- योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक तथा जनपद स्तर पर जिला सहकारी बैंकों को नोडल एजेंसी नामित किया जाता है। जनपद स्तर पर जिला सहायक निबन्धक के माध्यम से वितरित ऋणों का मासिक विवरण राज्य सहकारी बैंक को प्रस्तुत किया जायेगा जिसके द्वारा समग्र संकलित विवरण सहित अनुदान व प्रतिपूर्ति की मांग निबन्धक तथा नाबार्ड को तैमासिक/अर्धवार्षिक आधार अथवा उनके द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार प्रस्तुत की जायेगी। निबन्धक सहकारी समितियों द्वारा अपने स्तर पर भी समीक्षा कर नियमानुसार अनुमन्य अनुदान की मांग प्रत्येक त्रैमास में वितरित किये गये ऋणों के सापेक्ष राज्य सरकार व भारत सरकार से की जायेगी।

4- सहकारी सहभागिता योजना का नियोजन विभाग द्वारा कराए गए मूल्यांकन अध्ययन के क्रम में विभागाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित कार्यवाहियां सुनिश्चित की जायेगी:-

1. निबन्धक, सह0समि0 मुख्यालय व जिला सहकारी बैंक तथा विकास खण्ड स्तर पर आंकड़ों का रख-रखाव विधिवत रखना सुनिश्चित किया जाए।
2. मुख्यालय स्तर, जिला स्तर व विकास खण्ड स्तर पर अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
3. योजनान्तर्गत रोजगारपरक योजनाओं यथा-औद्यानिकी, मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण, मौन पालन, जड़ी-बूटी की खेती, सगन्ध के अन्तर्गत गुलाब की खेती व रेशम उत्पादन योजनाओं के लिए ऋण स्वीकृति हेतु सम्बन्धित विभागों से समन्वय रखकर ऋण वितरण करना सुनिश्चित किया जाए।
4. आवास ऋण योजना हेतु ऋण वितरण सहकारी समिति के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि अनुमन्य अनुदान प्राप्त हो सके। सहकारी सहभागिता योजना का सम्पूर्ण संचालन सचिवों द्वारा सम्पादित किया जाता है, कार्य हित में सहकारी समितियों के सचिवों के रिक्त पद भरे जाएं।
5. सहकारी सहभागिता योजना को कृषि यंत्र वितरण योजना से डबटेल कर दिया जाए।

योजना के संगत दिशा-निर्देश तथा वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

(सुबर्दन)
सचिव।

संख्या:-1646 (1)/XIV-1/2012, तददिनांक,

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, एफ0आर0डी0सी शाखा/सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, प्लॉट न0 सी0-24, ब्लॉक जी, पोस्ट बैग न0 8121 बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, मुम्बई (51)।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
10. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
12. वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(यू0सी0कबडवाल)
अपर सचिव।